संपादकीय जागरण

बुधवार, 20 सितंबर, 2017 : आश्विन कृष्ण अमावस्या वि. 2074

शिखर पर सदैव स्थान होता है बस उसके लिए प्रयास करते रहें

स्वच्छता अभियान की गति

स्वच्छ भारत अभियान को और गति देने के लिए खुद प्रधानमंत्री के स्तर पर लगातार जैसे प्रयास किए जा रहे हैं उससे यदि कुछ स्पष्ट होता है तो यही कि वह इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह देश को साफ-स्वच्छ बनाने के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ करते या कहते दिखते हैं। वह इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए न केवल आम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि अपने सहयोगी नेताओं को भी। इसी सिलसिले में हाल में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं का जो आयोजन किया गया उनके विजेताओं को गांधी जंयती के दिन सम्मानित करने की तैयारी हो रही है। चूंकि तीन वर्ष पहले दो अक्टूबर के दिन ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी इसलिए इसका भी आकलन किया जाना चाहिए कि आखिर इन तीन सालों में यह अभियान कितना आगे बढ़ा? तीन साल का लेखा-जोखा कैसी भी तस्वीर सामने लाए, राजनीतिक नेतृत्व और साथ ही आम जनता को यह समझना होगा कि देश को साफ-सुथरा बनाने का लक्ष्य न तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम है और न ही किसी दल विशेष का अभियान। देश को साफ-सुथरा बनाना हर किसी का उद्देश्य होना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब आम लोग अपने आसपास साफ-सफाई के लिए सजग एवं सक्रिय होंगे। निःसंदेह सरकार की तमाम कोशिशों के चलते आम जनता के स्तर पर एक हद तक साफ-सफाई के प्रति सजगता का भाव तो नजर आने लगा है, लेकिन अभी वैसी सक्रियता का परिचय नहीं दिया जा रहा है जो अपेक्षित ही नहीं, बल्कि आवश्यक भी है।

साफ-सफाई के प्रति सचेत रहना केवल इसीलिए जरूरी नहीं कि इससे हमारे सार्वजनिक स्थल गंदगी से मुक्त दिखेंगे। यह इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे ही पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी और इस तरह हमें अनेक गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। गंदगी के कारण रह-रहकर सामने आने वाली बीमारियां उत्पादकता पर बुरा असर डालने के साथ ही देश की छवि को भी खराब करने का काम करती हैं। अब साफ-सफाई को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा का सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है। यह अच्छा हुआ कि सर्दियां करीब आते ही केंद्र सरकार ने उन राज्यों को सचेत किया जहां के किसान फसलों के अवशेष यानी पराली जलाते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण की रोकथाम केवल पराली जलाने पर रोक लगाकर ही नहीं की जा सकती। पराली से खाद या फिर धुआं रहित जलाऊ ईंधन बनाने के साथ-साथ अन्य अनेक उपाय भी करने होंगे। ये उपाय सफल तब होंगे जब जनता उनकी उपयोगिता समझेगी। जिस तरह वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले सभी कारणों का निवारण करने की जरूरत है वैसी ही जरूरत जल प्रदूषण की रोकथाम के मामले में भी है। जलस्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। प्रधानमंत्री वर्ष 2022 तक एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं जो गंदगी और कचरे से मुक्त हो। बिना जन सहयोग इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं। विभिन्न देशों के उदाहरण भी यही कहते हैं कि साफ-सफाई का अभियान केवल शासन-प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

श्वेत पत्र

उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की योगी सरकार को पदारूढ़ हुए छह महीने हो चुके हैं। एक दिन पहले सरकार ने पंद्रह वर्षों (2003 से 2017) की सरकारों के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी किया। इस अवधि में समाजवादी पार्टी की दो बार और बहुजन समाज पार्टी की एक बार सरकार बनी। श्वेत पत्र बताता है कि इस दौरान दोनों पार्टियों की कार्यनीति का खमियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली बताने को यह आंकड़ा पर्याप्त है कि परिषदीय स्कूलों की छात्र-छात्राओं की संख्या में पांच वर्ष में 23.62 लाख की कमी आई है। साढ़े सात हजार विद्यालय आज भी इकलौते शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि साढ़े पैसठ हजार विद्यालयों में मानक से अधिक शिक्षक हैं। इन विद्यालयों में जरूरी सुविधाओं का कतई अभाव है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नकल पर प्रभावी अंकुश न लगाने से शिक्षा की गुणवत्ता गिरी है। स्वास्थ्य विभाग की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है, बिना काम के भुगतान किए गए और दूसरी ओर डाक्टरों के 40 प्रतिशत पद खाली हैं। दवा खरीद का सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा था।

बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, सड़क, परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में योगी सरकार बुनियादी कार्य कर रही है

श्वेत पत्र में बताया गया कि राज्य के सरकारी खजाने में बिना पैसे के ही कुछ लोगों के लाभ के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की जाती रहीं। भर्ती आयोगों ने पक्षपात तथा अनियमितताओं की पराकाष्ठा पार की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण धन उगाही का केंद्र बन गए, छोटे-बड़े उद्योगों के प्रतिकूल माहौल बना और आम किसानों, गन्ना किसानों की घोर उपेक्षा की गई। बिजली देने में घोर भेदभाव बरता गया। सरकारी और निजी भूमि पर कब्जे, भू-माफिया के दुस्साहस, कानून-व्यवस्था की तस्वीर सामने रखी गई। यह रिपोर्ट बताती है कि पटरी से उतर चुकी व्यवस्था को दुरुस्त करने में ही इस सरकार को काफी मेहनत करनी है। छह माह में इस सरकार ने इस दिशा में गंभीर प्रयास किए भी हैं। उम्मीद है कि आने वाले साढ़े चार साल में यह सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने में कामयाब होगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्दों का प्रयोग उनकी हताशा को जाहिर करता है?

आज का सवाल

क्या आप सरकार के इस रुख से सहमत हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों से देश की सुरक्षा को खतरा है?

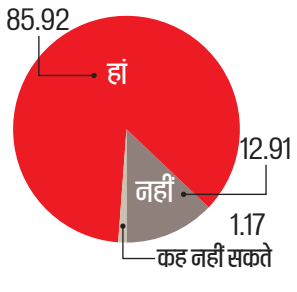

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

इंसानियत पर दोहरा रवैया

तसलीमा नसरीन

विदेश से आए मुस्लिमों के लिए तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू हैं, परंतु देश में प्रगतिशील युवकों की हत्या होने के बाद भी वह मौन हैं

शेख हसीना जी, सुना है आप रोहिंग्या मुसलमानों के दुख से दुखी हैं। जब पूरे विश्व का कोई भी देश इस धरती के सबसे अधिक प्रताड़ित जनसमूह को आश्रय नहीं देना चाहता तब आप उन्हें शरण दे रही हैं। इसी कारण आपकी तुलना जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ होने लगी है। भारत में 40 हजार रोहिंग्या मुसलमानों ने प्रवेश किया है। भारत सरकार का कहना है कि वे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं, इसलिए वह उन्हें बाहर करना चाहती है। रोहिंग्या को पाकिस्तान भी शरण देने को तैयार नहीं है। अमीर मुस्लिम देश भी उन्हें शरण नहीं दे रहे। जो देश मुसलमानों के लिए मातम मनाते हैं उन्होंने भी उनसे मुंह फेर लिया है। मुस्लिम कट्टरपंथी देश रोहिंग्या को लेकर शोर तो मचा रहे हैं, पर वे उन्हें शरण नहीं दे रहे। बांग्लादेश जैसे गरीब देश को अंतिम घड़ी में आगे आना पड़ा। शेख हसीन जी आपको नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठी है। वैसे नोबेल पुरस्कार मुझे मुग्ध नहीं करता। कई अयोग्य व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हेनरी किसिंग्जर जैसे अशांतिप्रिय को भी नोबेल दिया गया और आंग सान सू जैसी मानवाधिकार में विश्वास न करने वाली महिला को भी। पुरस्कार पाने के उद्देश्य से कोई अच्छा कार्य करना और पुरस्कार पाने की अभिलाषा के बिना असहाय लोगों के साथ निःस्वार्थ भाव से खड़ा होना, दोनों अलग बातें हैं। हम लोगों को विश्वास है कि आप पुरस्कार की उम्मीद लिए पीड़ित लोगों का साथ नहीं दे रही हैं। सच कहूं तो लोगों का प्रेम ही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है। धरती के सबसे उत्पीड़ित और निराश्रित लोगों का जो प्रेम आपको मिला है उसके सामने नोबेल जैसा पुरस्कार भी तुच्छ है।

आप कहती हैं, 'देश की 16 करोड़ जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा चुकी है और म्यांमार से आए लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को भी बांग्लादेश भोजन दे सकता है। विपदा में फंसे पांच-सात लाख लोगों को खाना देने की क्षमता हममें है।' ऐसी बातें विश्व के अमीर देश अब तक नहीं बोल सके हैं। ये बातें एक दरिद्र देश बांग्लादेश ने बोली हैं। आपने यह भी कहा कि 'म्यांमार के शरणार्थियों की तब तक हर संभव मदद करेंगे जब तक वे अपने देश नहीं लौट जाते।' ऐसी बातें आज कौन बोलता है! रोहिंग्या में से कइयों के इस्लामिक आतंकी होने की बातें कही जा रही हैं। उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। यहां तक कि मुसलमानों के लिए बना देश पाकिस्तान भी उन्हें नहीं चाहता। रोहिंग्या को आतंकी बनाने की मंशा लिए आतंकी आका बांग्लादेश में ही भूमिगत हैं, परंतु आपने कहा है कि यदि इन तत्वों ने मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी सहनशीलता का जवाब नहीं। जहां हर देश रोहिंग्या को दूर से ही भगा रहे हैं वहीं आप उन्हें सीने से लगा रही हैं। मुस्लिम देश आम तौर पर शरणार्थियों को शरण नहीं देते। अरब के लाखों असहाय शरणार्थियों के लिए अरब देशों के ही दरवाजे बंद होने पर वे यूरोप के देशों में शरण ले रहे हैं। मुस्लिम शरणार्थियों को आश्रय गैर इस्लामिक देश देते हैं, परंतु एक मुस्लिम देश की ओर से सिर्फ आपने ही यह दिखाया कि एक मुस्लिम देश भी लाखों प्रताड़ित मुसलमानों को आश्रय दे सकता है। आप कह रही हैं कि म्यांमार रोहिंग्या को वापस ले और उन्हें नागरिकता और सुरक्षा दे, परंतु आप भी जानती हैं कि कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, म्यांमार रोहिंग्या को वापस नहीं लेगा। वे लोग बांग्लादेश में ही रहते हुए अपने वंश का विस्तार करेंगे। अभाव से जूझने वाला एक विशाल जनसमूह चोरी, डकैती, छिनतई और मादक पदार्थों की बिक्री करेगा या फिर आतंकी समूहों से जुड़ जाएगा। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और आने वाले वक्त में भी बदस्तूर होती रहेंगी।

अवधेश राजपूत

आप कहती हैं कि 1975 में शरणार्थी के रूप में आपको विदेश में रहना पड़ा था इसीलिए आप शरणार्थियों का दुख समझती हैं, किंतु मैं नहीं समझती कि आप मेरा दुख समझती हैं। मुझे आपने शरणार्थी बनाकर रखा है। 24 वर्षों से मैं एक देश से दूसरे देश में जीवन बिता रही हूं। मेरा अपना देश है, परंतु मुझे अपने देश में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। मेरी किताब पर प्रतिबंध है। आप किताब पर भी प्रतिबंध समाप्त नहीं कर रही हैं। मैं अपनी बहन को पावर ऑफ एटार्नी देना चाहती हूं, लेकिन उस पर भी आपके विदेश सेवा के अधिकारी अडंगा डाल रहे हैं। एक जीवन में कोई व्यक्ति कितने अपमान, निषेधाज्ञा और अधिकारों से वंचित रह सकता है? जो उदार है उसे तो सबके लिए उदार होना चाहिए। क्या आप सबके लिए उदार नहीं हो सकतीं? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। किसी की हत्या नहीं की। कोई गड़बड़ी नहीं की। मैं तो मानवता और मानवाधिकार की ही बातें लंबे समय से कहती आ रही हूं। मुझे क्यों अछूत बना दिया? मानवता को किस ताक पर रखकर मेरे मुंह पर देश का दरवाजा बंद कर दिया गया? आप अभिव्यक्ति की आजादी में भी विश्वास नहीं करतीं? राजीव हैदर की हत्या का विरोध आपने किया था, परंतु आपने जब जाना कि राजीव नास्तिक था तो चुप हो गईं। देश में एक के बाद एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले प्रगतिशील ब्लॉगरों की हत्या हुई। आपने किसी की मौत पर शोक नहीं प्रकट किया। विदेश से आए मुस्लिमों के लिए आपकी आंखों में आंसू है, परंतु देश में प्रगतिशील और प्रतिभावान युवकों की हत्या होने के बाद भी आपकी आंखों में आंसू नहीं। आपने भयावह हत्याकांडों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। वे लोग नास्तिक थे इसीलिए आपने हत्याकांड की निंदा तक नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री, आप बार-बार भूल जा रही हैं कि आप आस्तिक और नास्तिक, दोनों की प्रधानमंत्री हैं। धनी-गरीब, नारी-पुरुष, हिंदू-मुस्लिम, नास्तिक-आस्तिक सभी के प्रति आपका समान दायित्व है। आपको सबको समान आंखों से देखना चाहिए।

कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वोट के लिए रोहिंग्या को शरण दे रही हैं। मुस्लिम वोट पाने का औजार हैं भी। रोहिंग्या यदि हिंदू या बौद्ध होते तो क्या आप उन्हें शरण देतीं? संभवतः नहीं। देश के भीतर ही हिंदू नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं और वे अपनी जमीन से ही बेदखल हो रहे हैं। उनके घर-बार जलाकर उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या आप इन हिंदुओं के पास गईं और आंखों से आंसू का एक कतरा भी बहाया? मुझे पता है कि बहुसंख्यकों का वोट पाने के लिए ही आप मुझे अपने देश में प्रवेश नहीं करने दे रही हैं और इसी कारण हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति तक नहीं दिखाती हैं। आप ब्लॉगरों की हत्या पर संवेदना भी व्यक्त नहीं करतीं, लेकिन दूसरे देश से आए शरणार्थियों के लिए पूरा प्रेम छलका रही हैं। वे मुसलमान हैं इसीलिए ऐसा कर रही हैं। सिर्फ चुनाव जीतना चाहती हैं। सिर्फ शासन करना चाहती हैं। जो छल-बल से सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें मुक्त स्वर में मानवतावादी कैसे बोला जाए।

(लेखिका जानी-मानी साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

अदालतों में हाजिरी लगाता शासन

राजीव सचान

व्यापक न्यायिक सक्रियता के बाद भी किसी मसले के अदालत जाने का अर्थ उसका निस्तारण हो जाना नहीं है

स्कूलों में फीस का मसला पहले से ही अदालतों के समक्ष पहुंच चुका था। अब स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का सवाल भी अदालतों तक पहुंच गया। ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामी के कारण ही हुआ, क्योंकि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक छात्र की हत्या के बाद यह पता चल रहा कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नियम-कानून ही नहीं और जो हैं भी वे अपर्याप्त और निष्प्रभावी हैं। रेयान स्कूल में छात्र की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने के आदेश दिए हैं। मामले की गंभीरता देख सरकार ने भी विभिन्न विभागों के सचिवों को मिलाकर एक समिति गठित कर दी है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। ऐसी जरूरत न जाने कितनी बार महसूस की गई, लेकिन राज्य सरकारों और साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे सभी को रेयान स्कूल की घटना का इंतजार था? पिछले वर्ष जनवरी में इसी स्कूल की दिल्ली शाखा में एक छात्र की टैंक में गिरकर मौत हो गई थी। उस मौत खबर भी सुर्खियां बनी थीं, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। नतीजा यह रहा कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि इस बच्चे की मौत कैसे हुई? हाल में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई। इस छात्र के माता-पिता धरना-प्रदर्शन करके जब हार गए तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। ये महज अपवाद के तहत आने वाले मामले नहीं हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब बेंगलुरु में एक के बाद एक स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण के मामले सामने आए थे। अभिभावकों ने तमाम धरना-प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा।

सरकारी अथवा निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा शासन एवं प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला मसला है, लेकिन अब इस मसले को भी सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ रहा है। यह शासन-प्रशासन के अधिकार क्षेत्र वाला एकलौता ऐसा मसला नहीं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा हो। इस तरह के न जाने कितने मामले हैं जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचते रहते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के वकील अब आए दिन अदालतों में खड़े दिखते हैं। निःसंदेह इसका एक कारण अदालतों की हर मामले को सुनने और सुलझाने की प्रवृत्ति भी है। इस प्रवृत्ति को इसलिए और बढ़ावा मिल रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने बात-बात पर अदालत

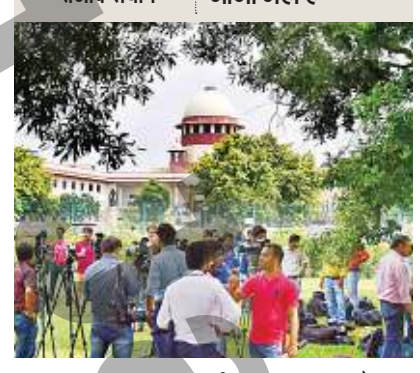

का दरवाजा खटखटाना अपनी आदत बना लिया है। कई लोग ऐसे हैं जो करीब-करीब हर दिन कोई न कोई जनहित याचिका लिए अदालत के समक्ष खड़े मिलते हैं। कई बार तो नीतिगत मसलों पर भी जनहित का सवाल उठाकर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया जाता है। रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में सरकार ने इतना ही कहा था कि वह उन्हें बाहर करेगी, लेकिन वह ऐसा कुछ करने का उपक्रम करती कि उसके पहले ही वकीलों की एक टोली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यह अदालती सक्रियता का दुर्लभ उदाहरण है। बीते कुछ समय से तो हालत यह है कि कोई कानून बनता बाद में है, उसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी पहले कर ली जाती है।

आधार कानून तो अदालत के समक्ष है ही, आधार संबंधी बिल को धन विधेयक में बदलने का फैसला भी अदालत के निर्णय की बाट जोह रहा है। ताजा-ताजा बना रेरा कानून भी अदालतों के समक्ष हाजिर है, लेकिन हर नियम-कानून और शासन-प्रशासन के फैसलों के अदालतों के समक्ष जाने के लिए केवल याचिकाबाज लोगों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति के लिए एक बड़ी हद तक खुद सरकारें और उनका प्रशासन भी जिम्मेदार है। भले ही सरकारें इस बात से परेशान हो गई हों कि न्यायपालिका उनके अधिकार क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाती जा रही है, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र वाले मसले अदालतों के सामने जा रहे हैं तो उनकी अपनी गलतियों के कारण।

किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई मामला अदालत में पहुंचने का मतलब उसका निस्तारण हो जाना है। यदि ऐसा होता तो गंगा न जाने कब साफ हो गई होती और हमारी पुलिस भी सुधर गई होती। पुलिस सुधार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के सात सूत्रीय दिशानिर्देशों पर दस साल बाद भी अमल नहीं हो पाया है और बीते दिनों जेलों में सुधार संबंधी 11 सूत्रीय दिशानिर्देश आ गए। जैसे सड़कों पर बने तमाम धर्मस्थल अभी भी अपने स्थान पर मौजूद हैं उसी तरह रात दस बजे के बाद सार्वजनिक स्थलों पर तेज ध्वनि वाले लाउडस्पीकर भी खूब सुनाई देते हैं। इसी तरह सरकारी बंगलों में तमाम अपात्र लोग भी अभी काबिज हैं। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड को रास्ते पर लाने की ठानी थी, लेकिन शायद ही किसी को यह लगता हो कि वह अपने मकसद में कामयाब है। जैसे लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि क्रिकेट बोर्ड को कौन चला रहा है वैसे ही यह भी कि सुप्रीम कोर्ट की काले धन वाली समिति क्या कर रही है? भले ही सुप्रीम कोर्ट से आए दिन ऐसी खबर आती हो कि उसने इन्हें-उन्हें फटकारा, लेकिन सच यह है कि कुछ लोग वर्षों तक अदालत-अदालत खेलते रहते हैं। एक नहीं अनेक मामले यही रेखांकित करते हैं कि अदालतें भी समस्या का समाधान करने में नाकाम हैं।

इस स्थिति का मूल कारण है प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ न्यायिक सुधारों की अनदेखी। जब तक इन दोनों सुधारों की अनदेखी की जाती रहेगी, आम लोगों की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। विडंबना यह है कि जैसे सरकार प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार नहीं दिखती वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक सुधारों के प्रति तत्पर नहीं नजर आता। सुप्रीम कोर्ट यह तो चाहता है कि चुनाव आयुक्तों और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हों, लेकिन ऐसी चाहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में नहीं दिखती। कहना कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए कैसे राजी किया जा सकता है कि वह न्यायपालिका में सुधार के लिए आगे बढ़े, लेकिन कम से कम सरकार और विशेष रूप से केंद्र सरकार को तो यह समझना चाहिए कि प्रशासनिक सुधारों की और अधिक समय तक अनदेखी करने का मतलब है खुद को समस्याओं से घेरना।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समस्या का समाधान

जैसे कक्षा पास करने के लिए इम्तिहान पास करने पड़ते हैं, उसी तरह जीवन के हर पड़ाव को पास करने के लिए समस्याओं के इम्तिहान भी पास करने पड़ते हैं। वे व्यक्ति जो विद्यार्थी भाव से सीखने की ललक, जिज्ञासा, उत्साह, लगन और कर्म करते हुए समस्याओं का धैर्य के साथ सामना करते हैं, वे इम्तिहान में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं और इतिहास पटल पर भी अमर हो जाते हैं। वहीं वे लोग जो खीझते, चिड़चिड़ाते हुए और दूसरों को कोसते हुए समस्याओं से लड़ते हैं, वे किसी तरह पास तो हो जाते हैं, लेकिन उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, जो कर्मठ, धैर्य, सकारात्मक और मुस्कराहट के साथ समस्याओं से जूझने वाले लोग कर पाते हैं। जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याएं हैं तो जीवन है। जीवन और समस्याएं एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं और इनके साथ गुंथे रहकर चलने से ही जीवन का आनंद आता है। जहां समस्याओं को अलग करने का प्रयास किया जाए तो वहां जीवन निढाल हो जाता है, मर जाता है और कृत्रिम हो जाता है।

व्यक्ति के हर पड़ाव पर आने वाली समस्याएं, कठिनाइयां, आघात, बीमारियां-ये सब जीवन के इम्तिहान हैं। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं कि, 'हमारे काम में देर-सवेर संकट आते ही हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र संकट से अछूता नहीं है। इसका सामना किए बगैर और इससे निजात पाए बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते।' समस्याओं से भागना वह दौड़ है, जो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि समस्याएं हमेशा आएंगी ही। अक्सर संकट या समस्या पहले से कहकर नहीं आती। इसकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती और सबसे अहम व बड़ी बात यह है कि समस्याओं से जूझने की क्षमता को उसी समय सीखा और सुलझाया जा सकता है, जब वे वास्तविक रूप से सामने आ जाती हैं। हम समस्याएं सुलझाने का कृत्रिम प्रयास बेशक कर लें, लेकिन वास्तविक प्रयास का परिणाम तो तभी सामने आता है जब समस्याएं पड़ने पर उनका सामना किया जाता है। जो व्यक्ति समस्याओं को देखकर मैदान नहीं छोड़ते और उनका डटकर मुकाबला करते हैं, वे उन्हें पराजित भी कर देते हैं। वहीं जो समस्याओं से डरकर भागने लगते हैं, समस्याएं दोगुनी तेजी से उनका पीछा करने लगती हैं।

रेनू सैनी

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

गुरु बिन ज्ञान कहां

खेल जगत में कुछ खास होने की उम्मीद शीर्षक से लिखे अपने लेख में शिवेंद्र कुमार सिंह ने देश में सभी खेलों के लिए प्रशिक्षित कोच की जरूरत पर बल दिया है। गुरु बिन ज्ञान कहां, किसी भी क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए गुरु की अवश्यकता होती है। हर कामयाब इंसान के पीछे उसके गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश में प्रतिभाशाली और होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ उन्हें पहचानने और तराशने की। खेल मंत्रालय को चाहिए कि वह हर जिला मुख्यालय में एक खेल संस्था खोले और जिन खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रर्दशन किया है उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आर्थिक मदद दे ताकि वे कोच बनकर देश में खिलाड़ियों की फौज तैयार कर सकें।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

शिक्षा का दामन कलंकित न हो

भारत में हमेशा से गुरुकुल परंपरा रही है जहां आचार्य शिष्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रहते थे। लेकिन अब स्कूल हैं जहां शिक्षा का व्यापार होता है। और शिक्षक सर्वांगीण विकास नहीं शोषण करते हैं। अभी प्रद्युम्न की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि जगदलपुर व बुलंदशहर में फीस न भरने के कारण तीन छात्रों को बंधक बना लिया, देवरिया में स्कूल की तीसरी मंजिल से गिर कर छात्रा की मौत, सीकर में दो शिक्षकों ने स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और जब छात्रा गर्भवती हो गई तो उसका जबरन गर्भपात कराया। लगातार हो रहीं ऐसी घटनाओं ने अभिभावकों की नींद उड़ा रखी है। अभिभावक जैसे-तैसे मोटी फीस का जुगाड़ कर अपने बच्चों अच्छे भविष्य के लिए निजी स्कूल का रुख करते हैं। और जब स्कूल में बच्चा सुरक्षित न हो तो ऐसे में वह कहां जाएं। ऐसे निजी स्कूलों का सबक सिखाने व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी होगी ताकि शिक्षा का दामन इस तरह कलंकित न होने पाए।

vermaranjit1946@gmail.com

हम शरण क्यों दें?

अभी देश में रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने को लेकर बहस छिड़ी है। कुछ पार्टियां शरणार्थियों को शरण देने की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देश को भी कुर्बान कर सकते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देना तो उनके वोट बैंक में चार चांद लगा देगा। जो अभी उनके लिए कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, उन्हें शरण देने के लिए रास्ते जाम कर रहे हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले समय ये शरणार्थी देश के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। जनसंख्या को देखते हुए देश में संसाधनों की पहले से ही कमी है, ऐसे में बाहरी लोगों को शरणार्थियों को रखना बहुत मुश्किल होगा।

pathaknirajkumarw®vx@gmail.com

खतरा बनेंगे रोहिंग्या

म्यांमार से बड़ी तादाद में खदेड़े जा रहे रोहिंग्या मुसलमान छोटी-छोटी नावों में भरकर समुद्र के रास्ते आ रहे हैं। नाव नहीं मिलती है, तो गले तक पानी में चलकर आने को मजबूर हैं। करीब तीन लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण लेने पहुंचे जहां राहत सामग्री की भारी कमी है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे व बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है। शरणार्थी शिविरों में ही औरतें बच्चों को जन्म दे रही हैं। कुछ रोहिंग्या भारत में भी आ रहे हैं जबकि जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर सहित विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से रह रहे हैं। यह चिंता का विषय है इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं पर देश की सुरक्षा को भी तो नहीं नकारा जा सकता है।

amitji5000@gmail.com

विश्व मंच पर उभरते खिलाड़ी

'खेल जगत में कुछ खास होने की उम्मीद' शीर्षक से लिखे लेख में लेखक शिवेंद्र कुमार सिंह ने भारत में खेल जगत के क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ियों की बड़ी उपलब्धियों को सराहनीय बताया है साथ ही खेल के क्षेत्र में आवश्यक सुधार की उम्मीद जताई है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर विश्व स्तर तक खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को लेकर विभिन्न खेलों में जीत का बिगुल बज रहा है। यह जीत खिलाड़ियों के साथ ही उनके कोच की भी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ी विश्व मंच पर भारत को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दे रहे हैं, लेकिन खेल प्रबंधन के क्षेत्र में आज भी हमारा देश बहुत पीछे है। जिसकी मुख्य वजह प्रशासकों की आपसी नोंक-झोंक है। जिसका प्रभाव हमारे खिलाड़ी पर भी पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर स्वयं एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी रह चुके हैं। वह खिलाड़ियों की विभिन्न आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित हैं। इसीलिए उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उम्मीद जताई है। यह सराहनीय है पर सवाल यह है कि आखिर उम्मीद कब पूरी होगी? या फिर यूं ही खिलाड़ियों को अपनी जरूरतों से समझौता करना पड़ेगा? माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह भारतीय खिलाड़ियों की विभिन्न खेल संबंधित जरूरतों को अपनी जरूरत मानकर उन्हें पूरा करें ताकि हमारे खिलाड़ी यूं ही विश्व में देश का परचम लहराते रहें।

ankitkunwar8899@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

ओवैसी कहते हैं कि रोहिंग्या मसला इस्लामी नहीं, बल्कि इंसानियत से जुड़ा है। अतीत में आखिर उन्होंने कितने गैर-मुस्लिम इंसानियत वाले मसले उठाए हैं।

सुशांत सरीन@sushantsareen

रोहिंग्या शरणार्थियों में चरमपंथी तत्वों की सूचना को देखते हुए सभी पर पाबंदी लगाना कितना वाजिब है। एलटीटीई ने एक भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी तो क्या हमने सभी श्रीलंकाई तमिलों को वापस भ